



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या १९ पटना, बुधवार, २३ वैशाख १९३७ (श०)
१३ मई २०१५ (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क
	5-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी 2015

सं० यो०३/३-१६/९९-६०६/यो०वि०—मंत्री, योजना एवं विकास विभाग को बिहार राज्य योजना पर्षद् के उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, ०८—५७१+१०-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचनाएं

15 अप्रैल 2015

अ0सं0-01-बी0एम0डी0-180-17 / 99-1266 / एम0—बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0 के निदेशक पर्वद को तत्कालिक प्रभाव से लगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है।

1. श्री शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।अध्यक्ष
 2. श्री शिशिर सिन्हा,
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0
बिहार, पटना।सरकारी सदस्य
 3. श्री शैलेश ठाकुर,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।सरकारी सदस्य
 4. श्री एच0आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।सरकारी सदस्य
 5. श्री बी0ए0खान,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।सरकारी सदस्य
2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 हसनैन खॉ, संयुक्त सचिव

सं० प्र0-1-प्रो0-04/2010-1443-एम०

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

30 अप्रैल 2014

खान एवं भूतत्व विभाग में राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को ए0सी0पी0 एवं रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3/एम0-2-5पी0 आर0-28/99-4685 वि0 (2) दिनांक 25.06.2003 एवं अधिसूचना संख्या 3ए-2 वे0पु0-18/09-7549 दिनांक 13.07.2010 के आलोक में निम्न प्रकार विभागीय स्क्रीनिंग समिति पुनर्गठित की जाती है।

(1) प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

अध्यक्ष

- (2) संयुक्त सचिव-सह-निदेशक-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदा0) सदस्य
- (3) अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग सदस्य
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अनु0 जाति सदस्य
/जन जाति के प्रतिनिधि।
- i. यह समिति ए0सी0पी0 / रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के तहत प्रोन्नति की कार्रवाई करेगी।
 - ii. स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। प्रथम आधे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामले को ए0सी0पी0 एवं रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के अधीन लाभ देने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचारणी होगा और उसी प्रकार द्वितीय आधे वित्तीय वर्ष (अक्टूबर से मार्च) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति विचार करेगी।
 - iii. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेशानुसार, समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी आहूत की जा सकेगी।
- (6) इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प 1563/एम0, दिनांक 07.06.13 को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाहरणालय, सुपौल
(स्थापना शाखा)

आदेश

15 सितम्बर 2014

सं० 1168-2/स्था०—अपर सचिव, वित्त विभाग के ज्ञापांक 2215 दिनांक 27.02.2012 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 544 स्था० दिनांक 03.03.2012 द्वारा श्री माधव मल्लिक, तात्कालीन लिपिक, नालन्दा कोषागार सम्प्रति अंचल कार्यालय, त्रिवेणीगंज जिला सुपौल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र “क” साक्ष्य सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है तथा अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4370 वि० (2) दिनांक 18.04.2012 द्वारा श्री मल्लिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं कृत कार्रवाई से वित्त विभाग को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 856-2 स्था०, सुपौल दिनांक 28.05.2012 द्वारा श्री माधव मल्लिक, लिपिक, अंचल कार्यालय, त्रिवेणीगंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री केदारनाथ, अपर समाहर्ता (राजस्व), सुपौल को संचालन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री केदार नाथ, अपर समाहर्ता, सुपौल के स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यालय ज्ञापांक 888-2 स्था० सुपौल दिनांक 30.05.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री अरुण कुमार, अपर समाहर्ता, सुपौल को संचालन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री माधव मल्लिक, लिपिक, अंचल कार्यालय त्रिवेणीगंज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र—“क”) पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक— 376-2 रा० सपत्र दिनांक 19.03.2014 द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में श्री मल्लिक के विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

श्री माधव मल्लिक, लिपिक, अंचल कार्यालय त्रिवेणीगंज के विरुद्ध गठित आरोप/आरोप के विरुद्ध आरोपी का स्पष्टीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी का मन्तव्य/संचालन पदाधिकारी की समीक्षा एवं प्रतिवेदन निम्न रूपेण उल्लेखित है:—

आरोप का विवरण

आरोप सं०-01 भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा-07 के अन्तर्गत रिश्वत लेने का दोषी होने के आरोप में बिहार थाना काण्ड संख्या 242/2002 दिनांक 17.07.2002 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

आरोप सं०-02 सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा को भंग करके बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)का उल्लंघन करना।

आरोप सं०-03 श्री मल्लिक द्वारा रिश्वत लेकर सरकारी कार्य का निष्पादन करने से नैतिक पतन उनका कार्याचरण परिलक्षित होना।

आरोप सं०-04 कार्यालय कार्य, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गम में कार्यालयीय कोताही (Official Delinquency) बरतना।

आरोप सं०-05 श्री मल्लिक द्वारा जान-बूझकर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में विलम्ब किया गया तथा रिश्वत ली गयी जिस कारण वे रंगे हाथ पकड़े गये। अतः श्री मल्लिक इस कदाचार एवं रिश्वत खोरी में लिप्त रहे हैं।

उपस्थापन पदाधिकारी का मन्तव्य

कोषागार पदाधिकारी-सह- उपस्थापन पदाधिकारी, सुपौल ने अपने पत्रांक 781/को० दिनांक 11.07.2012 के द्वारा निम्नांकित साक्ष्य के आधार पर मन्तव्य दिया गया है कि आरोपी श्री माधव मल्लिक के विरुद्ध कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा की गयी अनुशंसा एवं जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रपत्र“क” में कंडिका सं० 1 से 5 तक गठित आरोपों को सही अंकित किया गया है।

साक्ष्य की विवरणी:-

1. दिनांक 12.09.2002 को नालन्दा समाहरणालय में पदारूढ़ जिला पदाधिकारी श्री ई० हुकुम सिंह मीणा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापांक 1452 दिनांक 12.09.2002(जो प्रबन्ध निदेशक, औषधि एवं रसायन विकास लिमिटेड मौर्यालोक न्यू डाक बंगला रोड, पटना को सम्बोधित तथा कोषागार पदाधिकारी नालन्दा को प्रतिलिपि प्रदत्त है)
2. बिहार थाना काण्ड सं०-242/2002 दिनांक 17.07.2002 को दर्ज प्राथमिकी।
3. डॉ० मन्जुला सिंह द्वारा थाना प्रभारी बिहारशरीफ को दिनांक 17.07.2002 को समर्पित आवेदन पत्र।
4. थाना प्रभारी, बिहारशरीफ द्वारा न्यायालय में वाद समर्पण प्रपत्र-118/17.07.2002.
5. श्री माधव मल्लिक की जेब से बरामद(तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 100.00रु० के दो नोटों (OGV-271571 एवं OGV-271571)
6. पुलिस उपाधीक्षक, बिहारशरीफ के दिनांक 17.07.2002 की जप्ती सूची।
7. दिनांक 18.07.2002 माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी पटना को समर्पित अग्रसारण प्रतिवेदन।
8. तात्कालीन जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा दिनांक 17.07.2002 को निर्गत छापामारी आदेश।
9. तात्कालीन पुलिस अधीक्षक, द्वारा दण्ड प्र०सं० 173/174 के तहत दाखिल अन्तिम रिपोर्ट-बी-74265.
10. तात्कालीन जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति ज्ञापांक 2005/21.10.2002.

संचालन पदाधिकारी की समीक्षा:-

आरोपी कर्मचारी इस कार्यवाही में उपस्थित हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह कार्यवाही जून 2012 में ही प्रारंभ की गयी। आरोपी कर्मचारी ने आवेदन के माध्यम से एक माह के समय की मांग की। दिनांक 14.08.2012 को आरोपी कर्मचारी ने कारण पृच्छा समर्पित नहीं कर निगरानी न्यायालय में चल रहे आपराधिक कार्यवाही के लिए इस विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध किया। पुनः दिनांक 15.10.2012 को कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया। निगरानी विभाग के पत्रांक 2717 दिनांक 07.05.2011 की प्रति आरोपी कर्मचारी को देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि आपराधिक कार्यवाही के रहते विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी तथा उनसे पुनः कारण पृच्छा की मांग की गयी। आरोपी कर्मचारी ने कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया तथा जिला पदाधिकारी, नालन्दा से गठित आरोप पत्र (प्रपत्र-“क”) स्वच्छ प्रति अप्राप्त कहकर पुनः समय की मांग की। इस प्रकार वे बार-बार समय की मांग करते रहे।

इस तथ्य से अवगत कराने कि आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई साथ-साथ चल सकती है, के बावजूद सी०डब्लू०जे०सी० सं०-10645/2011 में दिनांक 21.03.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनः विभागीय कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध पर जिला पदाधिकारी का मन्तव्य प्राप्त हुआ कि विभागीय कार्यवाही चल सकती है, पुनः उन्हें अवगत करा दिया गया तथा फिर कारण पृच्छा की मांग की गयी।

दिनांक 25.04.2013 को इस बार उन्होंने आरोपों की स्वच्छ प्रति की मांग की। मांग किये जाने पर स्थापना उप समाहर्ता द्वारा छायाप्रति उपलब्ध कराया गया जिसे आरोपी ने पुनः अपठनीय बताया। मांग किये जाने पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने अपने पत्रांक 1660/स्था० दिनांक 21.10.2013 द्वारा स्वच्छ एवं स्पष्ट पठनीय प्रति उपलब्ध कराया, परन्तु आरोपी कर्मचारी की अमर्यादित व्यवहार की प्रकाष्टा तब रही जब उन्होंने अपना आरोप पढ़कर समझ लिया परन्तु इसकी प्रति लेने से इन्कार करते हुए इस कार्यालय के कार्यवाहक सहायक को कहा कि आरोप की प्रति उन्हें डाक से भेज दी जाय तथा लेने से इन्कार कर दिया। अतः न्यायहित में कार्यवाहक सहायक ने निबंधित डाक से उन्हें भेज दिया। दिनांक 17.01.2014 को वे उपस्थित होकर बताये कि उन्हें डाक नहीं मिला।

यह महसूस किया गया कि श्री माधव मल्लिक विभागीय कार्यवाही से बचना चाह रहे हैं, उन्हें अन्तिम बार चेतावनी दी गयी कि उनका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अब इस विभागीय कार्यवाही में आदेश पारित कर दिया जायगा।

तब उन्होंने दिनांक 10.02.2014 को साक्ष्यों की मांग की जो उन्हें कार्यालय द्वारा हस्तगत करा दिया गया, लेकिन कारण पृच्छा समर्पित नहीं किये।

दिनांक 07.03.2014 को आरोपी इस कार्यवाही में उपस्थित हुए परन्तु इस बार भी कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया तथा बताया कि वे सी० डब्लू० जे० सी० सं०-4875/2014 दायर किये हैं, अतएवं इस कार्यवाही को स्थगित रखने का पुनः अनुरोध किया। इस बार उनके इस टाल-मटोल के आचरण को देखते हुए उनका अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया तथा अभिलेख आदेशार्थ रखा गया।

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन :-

उपर्युक्त तथ्यों से विदित होता है कि आरोपी कर्मचारी आदेश की अवहेलना करनेवाले मनबदू प्रवृत्ति के अनुशासनहीन व नियंत्रण निरपेक्ष तथा सरकारी कर्मचारी के आचरण के विपरीत कार्य करनेवाले कर्मचारी हैं। इस कार्यवाही को **Avoid** करना तथा अपने बचाव में कुछ नहीं कहना सभी आरोपों की मूक स्वीकारोक्ति है।

अभिलेख में संलग्न सभी साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जिसके अध्ययन से विदित होता है कि आरोपी कर्मचारी ने डॉ० मंजूला सिंह जो स्वयं एक पदाधिकारी हैं, से रिश्वत लिया है, अतः उनकी स्पष्ट राय में आरोपी कर्मचारी श्री माधव मल्लिक के विरुद्ध गठित आरोप सत्य हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त संचालन/जाँच प्रतिवेदन एवं उनके मन्तव्य के साथ कार्यालय ज्ञापांक 705-2 सपत्र स्था० सुपौल दिनांक 11.06.2014 द्वारा आरोपी श्री माधव मल्लिक लिपिक, अंचल कार्यालय त्रिवेणीगंज से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री मल्लिक द्वारा अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री मल्लिक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथ्यपरक नहीं रहने के फलस्वरूप उसे अस्वीकृत किया जाता है।

समीक्षा

उपर्युक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त श्री मल्लिक लिपिक, कोषागार नालन्दा सम्प्रति अंचल कार्यालय, त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल के विरुद्ध नाजायज राशि लेने का आरोप प्रमाणित होता है।

निष्कर्ष:-

उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजातों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी के कारण पृच्छा के अवलोकन से आरोपी के विरुद्ध गठित नाजायज राशि लेने का आरोप सिद्ध होता है। यह आचरण सरकारी कार्य एवं कार्यालय की मर्यादाओं के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। श्री मल्लिक के विरुद्ध आरोप अत्यंत ही गंभीर श्रेणी में आता है जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के लिये यथेष्ट है।

अतः प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत मैं **लक्ष्मी प्रसाद चौहान, भा०प्र०से० जिलाधिकारी, सुपौल** श्री माधव मल्लिक, लिपिक, अंचल कार्यालय त्रिवेणीगंज को आदेश निर्गत होने की तिथि **15.09.2014** से सरकारी सेवा से **बर्खास्त (Dismiss)** करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से आज दिनांक 15.09.2014 को निर्गत किया गया।

श्री माधव मल्लिक से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. सरकारी सेवक का नाम :- श्री माधव मल्लिक
2. पिता का नाम :- स्व० दिगम्बर मल्लिक
3. स्थायी पता :- ग्राम- रामपुर पोस्ट-मधवापुर, जिला-मधुबनी,
4. जन्म तिथि :- 19.01.1956
5. पदनाम :- लिपिक
6. कार्यालय का नाम :- अंचल कार्यालय, त्रिवेणीगंज
7. नियुक्ति तिथि :- 02.09.1985

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सुपौल ।

15 सितम्बर 2014

सं० 1169-2/स्था०—जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल के कार्यालय में दिनांक 28.01.2006 को निगरानी विभाग, पटना द्वारा की गई छापेमारी के दौरान श्री चन्द्रहास वर्मा, तात्कालीन (सेवानिवृत्त) आशुलिपिक, जिला ग्रामीण विकास

अभिकरण, सुपौल (उप विकास आयुक्त सुपौल के कार्यालय) से अनुपस्थित रहने एवं उनके अलमीरा से 11600=00 (ग्यारह हजार छः सौ) रुपये पाये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के ज्ञापांक 71-2 स्था0 दिनांक 29.01.2006 के द्वारा श्री वर्मा से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 04.02.2006 तक अप्राप्त रहने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक 87-2 स्था0 दिनांक 04.02.2006 द्वारा श्री वर्मा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

संचालन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर श्री वर्मा निलंबित आशुलिपिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(V) के तहत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अधिरोपित करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 410-2/स्था0 दिनांक 08.04.2011 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1154-2/स्था0 सुपौल दिनांक 12.09.2011 से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3/एम0 91/2011-1983 दिनांक 14.06.2011 के कंडिका-11 के आलोक में निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानते हुए निलंबन अवधि का कर्तव्य वेतन देय नहीं होगा, दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-2634/2012 चन्द्रहास वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 05.03.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश "The matter is remanded to the disciplinary authority to proceed afresh in accordance with law from the stage of the submission of the enquiry report." के आलोक में की गयी सुनवाई, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध कागजातों, श्री वर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा एवं पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना से प्राप्त प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1627-2/स्था0 सुपौल दिनांक 25.11.2013 द्वारा उपरोक्त अधिरोपित दण्ड को यथावत रखा गया।

निगरानी धावादल द्वारा की गयी छापेमारी से संबंधित मामले की समीक्षा के क्रम में आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक 19-01/14-519 सपत्र/ वि0का0 सहरसा दिनांक 24.02.2014 से श्री चन्द्रहास वर्मा, आशुलिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका का आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा समीक्षोपरान्त दिनांक 22.02.2014 को उनके पारित आदेश का उद्धरण प्राप्त हुआ है।

पारित आदेश का उद्धरण-

सुपौल जिलान्तर्गत निगरानी विभाग द्वारा की गई छापेमारी के उपरान्त श्री चन्द्रहास वर्मा, आशुलिपिक, जिला कार्यालय सुपौल (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल में प्रतिनियुक्त) कर्म के विरुद्ध दिनांक 28.01.2006 को निगरानी विभाग के छापेमारी दस्ता के सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में श्री वर्मा द्वारा उक्त तिथि को वगैर किसी सूचना के अपनी आलमीरा में चाभी लगा छोड़कर भाग जाने एवं आलमीरा से रुपये 11600 (ग्यारह हजार छः सौ) रुपये पाये जाने एवं उक्त राशि को निगरानी विभाग द्वारा जब्त कर लिये जाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 87-2/स्थापना दिनांक 04.02.2006 द्वारा श्री वर्मा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया वो प्रपत्र "क" गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी वो जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 410-2/स्थापना दिनांक 08.04.2011 के द्वारा श्री चन्द्रहास वर्मा निलंबित आशुलिपिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम-14 (v) के तहत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया है वो कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1154-2/स्थापना दिनांक 12.09.2011 के द्वारा विभागीय कार्यवाही में श्री वर्मा को दोषी साबित पाये जाने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3/एम0 91/2011-1983 दिनांक 14.06.2011 की कंडिका 11 के आलोक में निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि नहीं मानते हुए निलंबन अवधि का कर्तव्य वेतन देय नहीं होने का आदेश पारित किया गया है।

जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 359-2/स्था0 दिनांक 20.02.2014 के द्वारा श्री चन्द्रहास वर्मा, आशुलिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संबंधी संचिका संख्या-32-09/06-14 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी है, में रक्षित कागजात का सुक्ष्म परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वर्मा को निगरानी विभाग द्वारा की गयी छापेमारी मामले में विभागीय कार्यवाही के दौरान दोषी पाया गया है। चूंकि मामला निगरानी ट्रेप से संबंधित है वो 11600.00 (रुपये ग्यारह हजार छः सौ) रुपये आलमीरा से मिलने के संबंध में आरोपी का आरोप संख्या-01 में यह स्वीकारोक्ति कि राशि के साथ मंदिर एवं क्रिकेट क्लब की चंदा का रसीद भी था (जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश के पृष्ठ-1 द्रष्टव्य)। यह स्पष्ट संकेत करता है कि आरोपी श्री वर्मा सरकारी कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध कार्य में लिप्त थे, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 13 "कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधि, या अन्य राशि जमा करने के लिए नकद या वस्तु रूप में चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसा काम में भाग लेगा" के प्रतिकूल है। श्री वर्मा को जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा दिया गया दण्ड अत्यन्त कम प्रतीत होता है। इतने गंभीर मामले में लघु दण्ड दिया जाना अधिरोपित आरोप तथा अभिलेख में जाँच के दौरान उभरे तथ्यों के तुलना में समुचित नहीं कहा जा सकता है।

वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 28 (ग) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस मामले का पुनः जाँच कर श्री वर्मा के विरुद्ध विधि सम्मत् तरीके से समुचित शास्ति पारित करने हेतु जिलाधिकारी, सुपौल को अभिलेख प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 473-2 स्था0 सुपौल दिनांक 07.03.2014 द्वारा श्री चन्द्रहास वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पूर्व से गठित आरोप पत्र पर नये सिरे से गहन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कुमार अरुण प्रकाश, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबन्धन, सुपौल को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शंभू कुमार, प्रभारी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 259-2 सपत्र/आ0प्र0 सुपौल दिनांक 29.04.2014 द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध गठित आरोप (प्रपत्र-“क”) पर विभागीय कार्यवाही का संचालन/जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

श्री चन्द्रहास वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल के विरुद्ध गठित आरोप/आरोप के विरुद्ध आरोपी का स्पष्टीकरण/संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/मन्तव्य निम्नरूपेण उल्लेखित है:-

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन:-

श्री चन्द्रहास वर्मा ने अपने उपस्थिति के साथ अपना स्पष्टीकरण दिया है कि पूर्व में संचालन पदाधिकारी और प्राधिकार को समर्पित कारण पृच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी उन्हें नहीं कहना है। उनके द्वारा समर्पित पूर्व कारण पृच्छा की छायाप्रति संलग्न है।

आरोप:-1

श्री वर्मा के विरुद्ध प्रथम आरोप है कि दिनांक 28.01.2006 को निगरानी ट्रैप के दौरान बिना किसी सूचना के अपनी आलमीरा में चाभी लगा छोड़ कर भाग गये। उनके आलमीरा से मो0 11600.00(ग्यारह हजार छः सौ) रु0 पाया गया, जिस राशि को निगरानी विभाग द्वारा जप्त कर लिया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-

श्री वर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि उन्होंने उप विकास आयुक्त, सुपौल से दूरभाष पर प्राप्त निदेश के अनुपालन में उनके निवास पर काम कर रहे थे उन्हें आलमीरा खुला छोड़ने की आदत सी थी और वे एक बार आलमीरा खोलने के बाद कार्यालय बन्द होने के समय ही अपना आलमीरा बन्द करते थे।

संचालन पदाधिकारी का मन्तव्य:-

मो0 11600.00(ग्यारह हजार छः सौ) रु0 आलमीरा से मिलने के संबंध में उन्होंने अंकित किया है यह मंदिर एवं क्रिकेट क्लब की राशि थी जिसका चंदे का रसीद भी था। मो0 11600.00 रु0 के संबंध में उनकी स्वीकारोक्ति की राशि के साथ मंदिर एवं क्रिकेट क्लब की चंदा का रसीद था। यह स्पष्ट संकेत करता है कि आरोपी श्री वर्मा सरकारी कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध कार्य में लिप्त थे जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 13 “कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधि, या अन्य राशि जमा करने के लिए नकद या वस्तु रूप में चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसा काम में भाग लेगा” के प्रतिकूल है। अतः उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या:-2

श्री वर्मा के विरुद्ध दूसरा आरोप है कि दिनांक 04.02.2006 को निगरानी दल का पुनः आगमन होने पर वे कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-

श्री वर्मा ने स्पष्टीकरण दिया है कि दिनांक 04.02.2006 को उन्होंने निलंबन आदेश प्राप्त किया। उन्होंने यह भी लिखा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय बन्द था और कार्यालय की सुरक्षा पुलिस कर्मी कर रहे थे।

संचालन पदाधिकारी का मन्तव्य:-

अंकित परिस्थिति में उन्होंने किस स्थान पर (कार्यालय/आवास/अन्य) अपना उक्त निलंबन आदेश दिनांक 04.02.2006 को प्राप्त किया, का उल्लेख अपने स्पष्टीकरण में नहीं किया है। अतः उनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

आरोप संख्या:-3

श्री वर्मा के विरुद्ध तीसरा आरोप है कि वे दिनांक 06.02.2006 को अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर को योगदान दिये और एक आवेदन देकर स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गये। अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा उस आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-श्री वर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि वे सरवाईकल स्पॉडिलाइटिस के मरीज हैं और बस से वीरपुर जाने के कारण उनके गर्दन में बहुत दर्द प्रारंभ हो गया और अपनी स्थिति बताकर चिकित्सा हेतु छुट्टी आवेदन समर्पित कर मुख्यालय से अनुपस्थित हुआ था।

संचालन पदाधिकारी का मन्तव्य:-

श्री वर्मा ने किस पदाधिकारी को अपनी स्थिति बताकर और किनसे अपना छुट्टी आवेदन स्वीकृत कराकर मुख्यालय से अनुपस्थित हुए, का उल्लेख अपने स्पष्टीकरण में नहीं किया है। जबकि नियमतः अवकाश आवेदन सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत कराकर अवकाश में जाने का प्रावधान है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त अवलोकन से श्री चन्द्रहास वर्मा के विरुद्ध चंदा मांगने एवं स्वीकारने और बिना अवकाश स्वीकृत कराये सरकारी कार्य से अनुपस्थित होने का दोष परिलक्षित होता है और उनको वृहत् दंड दिया जा सकता है।

आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा :-

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके मन्तव्य के साथ कार्यालय ज्ञापांक 691-2/स्था0 सुपौल दिनांक 05.06.2014 द्वारा आरोपी श्री चन्द्रहास वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल को निदेशित किया गया कि वे दिनांक 26.06.2014 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष द्वितीय कारण पृच्छा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। आरोपी निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना द्वितीय कारण पृच्छा प्रस्तुत किया। समर्पित कारण पृच्छा के अवलोकन एवं आरोपी को सुनने के पश्चात् पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित कारणों के अतिरिक्त कोई नया स्वीकारणीय तथ्य नहीं रखा गया है। अतः द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं रहने के फलस्वरूप उसे अस्वीकृत किया जाता है।

समीक्षा:-

उपर्युक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त आरोपी श्री वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल के विरुद्ध चंदा मांगने एवं स्वीकारने और बिना अवकाश स्वीकृत कराये सरकारी कार्य से अनुपस्थित रहने का दोष प्रमाणित होता है।

निष्कर्ष:-

उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजातों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी के कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित होते हैं। अतः श्री वर्मा को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ देना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है।

आदेश:- श्री चन्द्रहास वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल को प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत वृहद दण्ड स्वरूप शत- प्रतिशत (100%) पेंशन रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सुपौल।

28 जून 2014

सं० 835-2/स्था०—दिनांक 28.01.2006 को निगरानी विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल में की गई छापामारी के क्रम में श्री प्रभाकर लाल दास, (उच्च श्रेणी लिपिक) नाजिर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल के अलमीरा से मो० 2,52,158.70 (दो लाख बावन हजार एक सौ अठावन रुपये एवं सत्तर पैसे) अवैध पाये जाने एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिये जाने के फलस्वरूप आदेश ज्ञापांक-73-2/स्था० दिनांक 29.01.2006 द्वारा दिनांक 28.01.2006 के प्रभाव से श्री दास को निलंबित किया गया।

श्री दास के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा श्री दास के अलमीरा में अवैध रूप से पाये गये राशि मो० 2,52,158.70 (दो लाख बावन हजार एक सौ अठावन रुपये एवं सत्तर पैसे) के संबंध में प्रविवेदित किया गया है कि आरोपी अपने स्पष्टीकरण में सगे-सम्बन्धी से कर्ज के रूप में राशि लेने की बात कही है, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उक्त राशि को कार्यालय के अलमीरा में क्यों रखा गया जबकि शपथ-पत्र के अनुसार वर्णित राशि 28.01.2006 (निगरानी दल के छापामारी की तिथि) से बहुत पहले ही उन्हें प्राप्त हुई थी। अतः आरोप प्रमाणित पाकर कार्यालय ज्ञापांक 480-2/स्था० सुपौल दिनांक 28.04.2011 द्वारा श्री प्रभाकर लाल दास, उच्च श्रेणी लिपिक को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये गये:-

1. निलंबन की तिथि (28.01.2006) को प्रभावी वेतनमान 4500-125-7000 के न्यूनतम वेतन अर्थात् 4500.00 पर अवनति।

2. आगामी दो वर्षों तक वेतन वृद्धि देय नहीं होगा।

निगरानी धावादल द्वारा की गई छापेमारी से संबंधित मामले की समीक्षा के क्रम में आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल सहरसा के ज्ञापांक-19-2/14-527 सपत्र/वि०का० सहरसा, दिनांक 24.02.2014 से सुपौल जिलान्तर्गत निगरानी विभाग द्वारा किये गये छापेमारी के उपरान्त श्री प्रभाकर लाल दास, नाजिर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल के

अलमीरा से मो0 2,52,158.70 (दो लाख बावन हजार एक सौ अठावन रूपैये एवं सत्तर पैसे) अवैध पाये जाने के फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका का आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा समीक्षोपरान्त दिनांक 22.02.2014 को उनके पारित आदेश का उद्धरण प्राप्त हुआ है।

पारित आदेश का उद्धरण

सुपौल जिलान्तर्गत दिनांक 28.01.2006 को निगरानी विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल में की गई छापेमारी के उपरान्त श्री प्रभाकर लाल दास, नाजिर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल के अलमीरा से मो0 2,52,158.70 (दो लाख बावन हजार एक सौ अठावन रूपैये एवं सत्तर पैसे) अवैध पाये जाने एवं गिरफ्तार कर लिए जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 73-2/स्था0 दिनांक 29.01.2006 द्वारा श्री दास को दिनांक 28.01.2006 के प्रभाव से निलंबित किया गया वो प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी वो जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 480-2/स्थापना दिनांक 28.04.2011 के द्वारा श्री दास को निलंबन की तिथि 28.01.2006 को प्रभावी वेतनमान 4500-125-7000 के न्यूनतम वेतन अर्थात् 4500.00 पर अवनति एवं आगामी दो वर्षों तक वेतन वृद्धि देय नहीं होने का आदेश पारित किया गया है।

जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 359-2/स्था0 दिनांक 20.02.14 के द्वारा श्री प्रभाकर लाल दास, नाजिर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संबंधी संचिका संख्या 04-45/06-14 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी है, मैं रक्षित कागजात का सुक्ष्म परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री दास द्वारा आरोप संख्या-1 के संबंध में चार व्यक्ति का शपथ पत्र जो विभिन्न तिथियों में किया गया है संचिका के क्रमांक 70-73 पर रक्षित है के द्वारा कर्ज लेने संबंधी शपथ की छाया प्रति उपलब्ध कराया है जो After thought की ओर संकेत करता है। निगरानी ट्रैप का मामला दिनांक 28.01.2006 का है तथा शपथ पत्र दिनांक 13/12/08, 15/12/08 एवं 26/12/08 की तिथि में है। शपथ पत्र में कथन किए गये विन्दुओं की जाँच नहीं करायी गयी है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 17 (5) (क) के परन्तु में प्रावधानित है कि " कोई सरकारी सेवक अपने किसी सम्बन्धी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितान्त अस्थायी ढंग का व्याज रहित उधार दे सकेगा या उसे ले सकेगा अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा"। आरोपी कर्मी द्वारा बड़ी राशि रुपये 1,50,000.00 तक उधार के रूप में लेने की बात कही गयी है जो उक्त प्रावधान के प्रतिकूल प्रतीत होता है। कर्ज/उधार के रूप में ली गई राशि का कार्यालय के अलमीरा में रखना संदेह उत्पन्न करता है। श्री दास निगरानी विभाग द्वारा की गयी छापेमारी मामले में विभागीय कार्यवाही के दौरान दोषी पाये गये हैं। श्री दास को जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा दिया गया दंड कम है। चूंकि मामला निगरानी ट्रैप से संबंधित है। इतने गंभीर मामले में कम दंड दिया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 29 में निहित प्रावधान के आलोक में विलम्ब को क्षान्त करते हुए नियम 28 ग में प्रदत्त शक्तियों के तहत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 17 को दुष्टिगत रखते हुए इस मामले का पुनः जाँच कर श्री दास के विरुद्ध समुचित शास्ति पारित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को अभिलेख प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 472-2/स्था0 सुपौल दिनांक 07.03.2014 द्वारा श्री प्रभाकर लाल दास, उच्च श्रेणी लिपिक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा सुपौल समाहरणालय संवर्ग को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध पूर्व से गठित आरोप पत्र पर नये सिरों से गहन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी श्री कुमार अरुण प्रकाश, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन सुपौल तथा उपस्थापन पदाधिकारी श्री शम्भू कुमार, प्रभारी निदेशक, डी0आर0डी0ए0 सुपौल को नियुक्त किया गया तथा जाँच पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि जाँच प्रतिवेदन एक माह के अन्दर (मूल अभिलेख के साथ) अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त करावें।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 259-2/आ0प्र0 सुपौल दिनांक 29.04.2014 द्वारा श्री प्रभाकर लाल दास, पूर्व नाजीर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल के विरुद्ध पूर्व से गठित आरोप पत्र पर नये सिरों से विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आरोपवार आरोपी का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन का विवरण निम्न प्रकार है:-

आरोप संख्या-01:-

श्री दास के विरुद्ध प्रथम आरोप है कि दिनांक 28.01.2006 को निगरानी ट्रैप के दौरान उनके अलमीरा से मो0 2,52,158.70 (दो लाख बावन हजार एक सौ अठावन रूपैये एवं सत्तर पैसे) अवैध रूप से पाया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-

श्री दास ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि उन्होंने उक्त रकम अपने सगे संबंधियों से उधार (कर्ज) के रूप में अपनी पुत्री की शादी जो दिनांक 15.02.2006 को होना तय था के लिए लिया था। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०	कर्ज देने वाले संबंधी का नाम	राशि	कर्ज प्राप्त करने की तिथि
1	श्री हिरेन्द्र कुमार दास	25000.00	17.01.2006
2	श्री कांति कुमार वर्मा	45000.00	24.01.2006
3	श्री अशोक कुमार सिंह	32000.00	05.01.2006
4	श्री दिगम्बर लाल दास	150000.00	20.01.2006

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन:-

श्री दास द्वारा एक बड़ी राशि 150000.00 (एक लाख पचास हजार) रु० उधार के रूप में लेने की बात कही गयी है। जिसके संबंध में उन्होंने बतलाया कि श्री दिगम्बर लाल दास उनके बहनोई है और उन्होंने उक्त बड़ी रकम उन्हें अपने बैंक खाता से निकालकर दिया था। परन्तु उन्होंने संबंधित बैंक खाता के उक्त संचालन से संबंधी विवरणी की पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने पुनः बतलाया कि उक्त रकम उनके बहनोई ने जमीन बिक्री कर उससे प्राप्त रकम से दिया है। श्री दास से उक्त जमीन बिक्री के केवाला की विवरणी की मांग करने पर उन्होंने मेरे कार्यालय कक्ष से अपने मोबाईल से संबंधित पासबुक की छायाप्रति/केवाला की विवरणी की मांग अपने बहनोई से की, परन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दिया। बल्कि श्री दास ने टाल मटोल करते हुए कहा कि जमीन का बिक्री खिसटा केवाला के जरिये अथवा मौखिक हुआ है। श्री दास के द्वारा अपने पुत्री की पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम (तिलक दिनांक 30.01.2006 एवं शादी दिनांक 15.02.2006) संबंधी कोई पत्राचार/न्योता/शादी का कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत पुत्री के शादी का कार्ड दिनांक 05.07.2006 से संबंधित है। श्री दास के द्वारा प्रस्तुत उक्त चार व्यक्तियों से उधार लेने संबंधी शपथ पत्र, पुत्री के दिनांक 05.07.2006 के शादी कार्ड, मंगलम ड्रेसेज, सुपौल एवं श्री महावीर वस्त्र भंडार, सुपौल से उधार लेने संबंधी विपत्र सभी निगरानी ट्रैप दिनांक 28.01.2006 के बाद का है जो **After thought** की ओर संकेत करता है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 17 (5) (क) के परन्तु में प्रावधानित है कि “कोई सरकारी सेवक अपने किसी संबंधित या निजी मित्र को छोटी रकम का नितांत अस्थायी ढंग का ब्याज रहित उधार दे सकेगा या उसे ले सकेगा अथवा किसी वास्तविक व्यापारिक के साथ उधारी खाता चला सकेगा या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा”। श्री दास के द्वारा एक बड़ी राशि 150000.00 (एक लाख पचास हजार) रुपये अपने संबंधी बहनोई (श्री दिगम्बर लाल दास) से उधार के रूप में लेने की बात कही गयी है जो उक्त प्रावधान के प्रतिकूल प्रतीत होता है। अतः उनका यह स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या-02:-

श्री दास के विरुद्ध दूसरा आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत-करहिया, कमलपुर, बेला सिंगार, कर्णपुर, परसरमा-परसौनी एवं धरहरा का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक रोक कर रखा गया जिनके विरुद्ध भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त पायी गयी।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-

श्री दास ने स्पष्टीकरण दिया है कि उप विकास आयुक्त, सुपौल महोदय के निदेशानुसार चूँकि उक्त पंचायतों ने अपना वार्षिक कार्य योजना, इंदिरा आवास योजना की पाँच वर्षों की सूची, 2003-04 का अंकेक्षण का अनुपालन एवं 2004-05 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल में जमा नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप उक्त चेक/ड्राफ्ट तामिला नहीं करवाया गया था।

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन:-

आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है।

आरोप संख्या-03:-

श्री दास के विरुद्ध तीसरा आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना का 63 चेक एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का 45 चेक निर्गत हो जाने के पश्चात भी संबंधित एजेंसी एवं ग्राम पंचायतों को ससमय नहीं भेजा, इन चेकों की समय सीमा समाप्ति पर है।

आरोपी का स्पष्टीकरण:-

श्री दास ने स्पष्टीकरण दिया है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम के क्रमांक 01 से 63 तक के चेक दिनांक 14.01.2006 की तिथि में दिनांक 27.01.2006 को वरीय पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था क्योंकि सरकार को प्रतिवेदित करना था कि उक्त पद में मात्र राशि लगभग डेढ़ करोड़ व्यय होना शेष है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्गत क्रमांक 1 से 45 तक के चेक के संबंध में श्री दास ने स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ

पंचायतों द्वारा बिन्दु 02 में उल्लेखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करवाने तथा कुछ पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण के कारण कुल 180 पंचायतों में से मात्र 45 पंचायतों का चेक तामिला नहीं हो सका।

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन:-

विलंब होने का कारण परिस्थिति जन्य है, अतएव दास का इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष के रूप में प्रतिवेदित किया है कि श्री प्रभाकर लाल दास के विरुद्ध नजायज राशि लेने का दोष परिलक्षित होता है और इन्हें वृहत् दंड दिया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके मंतव्य के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 683-2/स्था0 सुपौल दिनांक 02.06.2014 द्वारा आरोपी श्री प्रभाकर लाल दास निलंबित उच्च श्रेणी लिपिक समाहरणालय सुपौल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके आलोक में श्री दास द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया। समर्पित कारण पृच्छा के अवलोकन से विदित होता है कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित कारणों के अतिरिक्त कोई नया स्वीकारणीय तथ्य नहीं रखा गया है। अतः द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।

समीक्षा:-

उपर्युक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त आरोपी श्री दास निलंबित उच्च श्रेणी लिपिक, तात्कालिन नाजीर डी0आर0डी0ए0, सुपौल के विरुद्ध नाजायज राशि लेने का आरोप प्रमाणित होता है।

निष्कर्ष:-

उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजातों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी के कारण पृच्छा के अवलोकन से आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप नाजायज राशि लेने का आरोप सिद्ध होता है। यह आचरण सरकारी कार्य एवं कार्यालय की मर्यादाओं के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। श्री दास के विरुद्ध आरोप अत्यंत ही गंभीर श्रेणी में आता है जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के लिये यथेष्ट है।

अतः प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत मैं **लक्ष्मी प्रसाद चौहान, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी, सुपौल** श्री प्रभाकर लाल दास, उच्च श्रेणी लिपिक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा सुपौल समाहरणालय संवर्ग, सुपौल को आदेश निर्गत होने की तिथि 28.06.2014 से सरकारी सेवा से **बर्खास्त (Dismiss)** करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से आज दिनांक 28.06.2014 को निर्गत किया गया।

श्री प्रभाकर लाल दास से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. सरकारी सेवक का नाम :- श्री प्रभाकर लाल दास
2. पिता का नाम :- स्व0 सुखदेव लाल दास
3. स्थायी पता :- ग्राम- कन्दाहा, पत्रालय- महिषी, थाना-महिषी, जिला- सहरसा
4. जन्म तिथि :- 26.06.1954
5. पदनाम :- उच्च श्रेणी लिपिक
6. कार्यालय का नाम :- सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल
7. नियुक्ति तिथि :- 15.11.1985

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सुपौल ।

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

7 अप्रील 2015

सं0 2/अ0प्र0-2-09/14-18—श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, अलीगंज, जमुई के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में दिनांक 11.12.2014 को बिना समाचार पत्र में निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित किये गुपचुप तरीके से 65,00,000/—(पैसठ लाख) रुपये का निविदा कर सरकार को लगभग ग्यारह-बारह लाख रुपये की क्षति पहुँचाने एवम् अपने चहेते संवेदकों को कार्य आवंटित करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में श्री संजय कुमार द्वारा माननीय लोकायुक्त कार्यालय में समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में माननीय लोकायुक्त के आदेश पर

तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गयी जाँच/माननीय लोकायुक्त की अनुशंसा, विभागीय जाँच एवम समीक्षा के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कुल 02(दो) आरोप गठित हैं, जिनका सार निम्नवत है:-

- (i) विषयान्तर्गत मामले में माननीय लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों एवम जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2004 को पटना जंक्शन पर दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स(अंग्रेजी) एवम प्रभात खबर (हिन्दी) समाचार पत्र विक्रेता से खरीदकर उसी दिन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में हस्तगत कराया गया। इस मामले में जाँचोपरान्त पाया गया कि वस्तुतः दिनांक 04.12.2004 को उपर्युक्त दोनों समाचार पत्रों को ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ से प्राप्त समबधित निविदा प्रकाशन हेतु जन-सम्पर्क विभाग द्वारा भेजा ही नहीं गया था। दोनों समाचार पत्रों जिनमें तथा कथित निविदा आमंत्रण सूचना छपे हैं, जाली पाये गये हैं। इस प्रकार, इनके विरुद्ध इस षडयंत्र में संलिप्त होने के लिए दोषी होने का आरोप प्रतिवेदित है।
- (ii) विभागीय पत्रांक 949 दिनांक 12.02.2008 एवम स्मार पत्रांक 3518, दिनांक 08.005.2008 द्वारा विषयान्तर्गत मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवम बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 के नियम 03 का उल्लंघन करने के लिए दोषी होने का आरोप प्रतिवेदित है।
- (iii) उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3404(एस) दिनांक 10.02.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित दोनों आरोपों को प्रमाणित बताया गया।
- (iv) तत्पश्चात पथ निर्माण विभाग के पत्र सं०-निग/सारा-6(आरोप द०वि०(ग्रा०) 145/2008 को पत्रांक 2666(एस) दिनांक 03.04.2014, पत्रांक 7407(एस) दिनांक 16.09.2013 द्वारा श्री कुमार के द्वारा बरती गयी अनियमितता के लिए सेवा से बर्खास्त के अनुमेदित दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।
- (v) पथ निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 6/प्रो०-24-07/2013(1568) लो०से०आ० दिनांक 22.10.2013 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अनुमोदन से संबंधित अवतरण की छायाप्रति की मांग की गई। जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि श्री कुमार श्रेणी दो के पदाधिकारी हैं तथा उनके विरुद्ध दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस मामले में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से इतर सक्षम प्राधिकार के निर्णय पर भी आयोग का परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।
- (vi) इस बीच पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8872 (एस) दिनांक 20.11.2013 द्वारा श्री संजय कुमार का कैडर विभाजन ग्रामीण कार्य विभाग किया गया है, अतः श्री कुमार के विरुद्ध पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण श्री कुमार से संबंधित आरोप की संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गयी।
- (vii) उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 702 अनु० दिनांक 26.02.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से श्री कुमार के सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर परामर्श/सहमति हेतु अनुरोध किया गया।
- (viii) बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के संचिका सं०-06/प्रो०-24-07/2013 (171) लो०से०आ० दिनांक 25.04.2014 द्वारा श्री कुमार के सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय दंड के बिन्दु पर सहमति दी गयी, जिसकी प्रति पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3684 (एस) दिनांक 13.05.2014 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी।
- (ix) श्री संजय कुमार की जन्म तिथि 04.01.1959, सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति की तिथि 18.08.1998 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2019 है।

उक्त आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, अलीगंज, जमुई को प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार

सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका-14 (X) के तहत बृहत् दंड सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव श्री संजय कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, अलीगंज, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14 (X) के तहत बृहत् दंड सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

श्री संजय कुमार द्वारा उन्हें दी गयी बर्खास्तगी की सजा पर पुर्नविचार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुर्नविचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा शास्ति के अधिरोपण में विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है।

अतएव विभागीय निर्णयानुसार श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति बर्खास्त का पुर्नविचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

10 अप्रील 2015

सं0 3/अ0प्र0-1-12/14-20—श्री गुफरान अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा अपने पदस्थापन काल में मधुबनी जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नागदह बलाईन पथ के सेतु निर्माण एवं अन्य योजनाओं में गंभीर अनियमितता बरती गयी। उक्त आरोपों के लिए श्री अहमद के विरुद्ध पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 5915 दिनांक 23.05.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन संचालित की गयी।

अभियंताओं के कैडर विभाजन के उपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7450 (एस0) डब्लू दिनांक 03.07.2012 द्वारा संबंधित संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को प्राप्त हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या 2705 दिनांक 11.08.2014 द्वारा श्री अहमद की सेवानिवृत्ति के उपरांत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय पत्रांक 2733 अनु0 दिनांक 13.08.2014 द्वारा श्री अहमद से द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री अहमद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अहमद के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत मिस कंडक्ट का मामला नहीं बनता है, जिससे सरकार को वितीय क्षति हुई हो।

अतः श्री गुफरान अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान से सहमत होते हुए श्री गुफरान अहमद को आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**